THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

NITIN SIR CLASSES

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

thursday, 25 Sep, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 01 Syllabus :GS 2 : Indian Polity / Prelims	लेह आंदोलन जानलेवा हिंसा में बदल गया; सरकार ने कार्यकर्ता को ज़िम्मेदार ठहराया
Page 04 Syllabus :GS 2 : International Relations / Prelims	ग्लोबलसाउथकोमिलकरकामकरनाचाहिए: जयशंकर
Page 06 Syllabus :GS 2 : Social Justice/ Prelims	केंद्रनेदेशभर में मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना को मंजूरी दी
Page 07 Syllabus :GS 3 : Science and Tech / Prelims	क्याएआईभारतकी ऊर्जा मांग को ठीक करेगा या उसकी खुद की जरूरतों को पूरा करेगा?
Page 11 Syllabus :GS 2 : Social Justice/ Prelims	जीवन, मृत्युऔरअंग दान के बारे में बातचीत कैसे शुरू करें
Page 09 : Editorial Analysis Syllabus :GS 3 : Disaster Management	बाढ़ से लड़ने के लिए कैलेंडर का नहीं, बल्कि बारिश का अनुसरण करें

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 01 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

24 सितंबर, 2025 को, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह शहर में जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का **दर्जा** और छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए । अशांति के कारण सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो गई, सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और हताहत हुए। 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू करने वाले जलवायु कार्यकर्ता **सोनम वांगचुक** की पहचान एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में की गई थी, जिसने युवाओं की लामबंदी को ट्रिगर किया था। विरोध प्रदर्शन राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता के लिए लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय आकांक्षाओं को रेखांकित करते हैं।

Leh stir explodes into deadly violence; govt. blames activist

BJP office torched and Ladakh Hill Council premises vandalised as protesters seeking Statehood, tribal status for region go on a rampage; Centre says an unruly crowd destroyed public property, attacked the police; 30 security personnel injured

Public outcry: A vehicle belonging to the security forces was set on fire during the protests in Leh demanding Statehood for the Union Territory of Ladakh, on Wednesday. AP

Vijaita Singh
Peerzada Ashiq
NEW DELHI/SRINAGAR

Several people were feared dead and many injured in Leh city in the Union Territory of Ladakh on Wednesday after an ongoing protest demanding the constitutional safeguards of Statehood and tribal status for the region bordering China turned violent.

The Union Home Ministry, in a statement, said an unruly mob destroyed public property and attacked the police, injuring around 30 security personnel. The police had to resort to firing, in which "unfortunately some casualties are reported", it said.

The Ministry said a hunger strike was started by climate activist Sonam Wangchuk on September 10 to press for Statehood and inclusion of Ladakh under the Sixth Schedule (tribal status). It said the Government of India had been actively engaging with the Leh Apex Body (LAB) and the Kargil Democratic Alliance (KDA), and despite a planned meeting on September 26 with the leaders, "a mob guided by Sonam Wangchuk's provocative statements" caused violence.

"The government stands committed to the aspiration of people of Ladakh by providing adequate constitutional safeguards," the Ministry said.

It added that the demands on which Mr. Wangchuk was on hunger strike were an integral part of the discussion of a high-powered committee.

'Mislead the people'

"In spite of many leaders urging to call off the hunger strike, he continued with the hunger strike and misleading the people through provocative mention of Arab Spring-style protest and references to Gen Z protests in Nepal... Amidst these violent developments, he broke his fast and left for his village in an ambulance without making serious efforts to control the situation," it said. The protesters, mostly youth, torched the BJP office and vandalised the Ladakh Autonomous Hill Development Council premises.

The Ministry added that the process of dialogue through the high powered committee had yielded phenomenal results, such as increasing reservation for Ladakh Scheduled Tribe from 45% to 84%, providing one-third reservation for women in the councils, and declaring Bhoti and Purgi as official languages. The process for recruitment for 1,800 posts had also commenced, the Ministry said.

Ladakh Lieutenant-Governor Kavinder Gupta, in a televised address, confirmed the deaths but did not specify the number, adding that curfew had been imposed as a precautionary measure.

"Deployment of security personnel was made in the wake of a shutdown call to maintain law and order in Leh. The security personnel were provided with *lathis* (batons). However, there was an attempt to burn down a CRPF vehicle with personnel in it. The vehicle of the Director-General of Police was attacked with stones," Mr. Gupta said.

On Tuesday, Home Ministry officials had called a delegation of seven leaders from Ladakh to Delhi on September 26 for a preliminary meeting. Cherring Dorjay Lakruk, the president of the Ladakh Buddhist Association (LBA), told *The Hindu*.

Mr. Lakruk, who is also the co-convener of the Leh Apex Body (LAB), which had been spearheading the protests, told *The Hindu* that a large number of people in the age group of 14-25 joined the protests on Wednesday, a day after two elderly protesters, who were on hunger strike along with Mr. Wangchuk for 14 days, were hospitalised.

Following the violence, Mr. Wangchuk called off the hunger strike. Addressing a virtual press conference, he said that "nobody had an inkling something like this will happen".

"Many leaders who came here said that peaceful protests are not enough. We never thought it will explode like this. Ladakh witnessed Gen Z frenzy today. They were not listening to anybody. They were not even afraid of bullets. This is the fifth time we have sat on a hunger strike. The youth said peaceful protests are not working... we were being told by the youth for the past few days," Mr. Wangchuk said.

RELATED REPORT
» PAGE 5

स्थैतिक संदर्भ (संवैधानिक और कानूनी ढांचा):

1. **केंद्र शासित प्रदेश और छठी अनुसूची:**
   - लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश **है** जहां विधानसभा नहीं है (जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद 2019 से)।
   - संविधान की छठी अनुसूची **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषदों और विशेष सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें भूमि, संसाधनों और स्थानीय शासन की सुरक्षा शामिल है।**
2. **स्वायत्त पर्वतीय परिषद:**
   - लद्दाख में लेह और कारगिल के लिए **लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी)** है , जो स्थानीय स्वशासन और विकास स्वायत्तताप्रदानकरतीहै।
   - वर्तमान वैधानिक प्रावधानों **में अनुसूचित जनजातियों**, **महिलाओं** के लिए कोटा और आधिकारिक भाषाओं **की मान्यता शामिल है**।
3. **भूख हड़ताल और सार्वजनिक विरोध:**
   - शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भूख हड़ताल लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के मान्यता प्राप्त रूप हैं, जो **अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित हैं - भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**।
   - हालांकि, **हिंसक विरोध प्रदर्शन** और संपत्ति को नष्ट करना आपराधिक अपराधों के अंतर्गत आता है, जिसे **आईपीसी की धाराओं और कानून-व्यवस्था नियमों द्वारा संबोधित किया जाता है**।

वर्तमान संदर्भ (तत्काल घटनाएँ):

दैनिक समाचार विश्लेषण

1. **ट्रिगर्स:**
   - सोनम वांगचुक के नेतृत्व में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची को शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल।
   - आरोप है कि "भड़काऊ बयानों" ने युवाओं को हिंसा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।
2. **प्रभाव:**
   - भाजपा कार्यालय में आग की हगरानी; एलएएचडीसी परिसर में तोड़फोड़ की गई।
   - करीब **30 सुरक्षाकर्मी घायल**, कर्फ्यू लगाया गया।
   - प्रदर्शनकारियों के बीच हताहतों की सूचना मिली; सटीक संख्या अपुष्ट।
3. **सरकार की प्रतिक्रिया:**
   - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की शीर्ष संस्था (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ बातचीतपरजोरदिया।
   - उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्रगति पर प्रकाश डाला गया:
     - लद्दाख अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण **45 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत** किया गया।
     - परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण।
     - भोटी और पुरगी भाषाओं **की मान्यता**।
     - 1,800 पदों **पर भर्ती प्रक्रिया शुरू**।
4. **युवा भागीदारी:**
   - अधिकांश प्रदर्शनकारी **14-25 वर्ष के थे**, जो **जेन जेड सक्रियता का संकेत देते थे**।
   - प्रक्रियात्मक संवादों और तत्काल राजनीतिक समाधान की इच्छा के साथ मोहभंग को प्रदर्शित करता है।

विश्लेषण

1. **शासन और प्रशासन:**
   - बड़ी युवा आबादी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले केंद्र **शासित प्रदेशों के प्रशासन की चुनौतियों पर** प्रकाश डाला
   - जनजातीय और स्थानीय मांगों को पूरा करने में **स्वायत्त परिषदों की सीमाओं को** दर्शाता है।
2. **संवैधानिक और राजनीतिक आयाम:**
   - राज्य की मांग **संघवाद, शक्ति के हस्तांतरण** और छठी अनुसूची के संरक्षण से संबंधित है।
   - यह घटना केंद्र शासित प्रदेशों में आदिवासी **समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों** पर सवाल उठाती है।
   - लोकतांत्रिक विरोध को **कानून और व्यवस्था** के साथ **संतुलित करना** शासन की एक लगातार चुनौती है।
3. **सामाजिक-आर्थिक संदर्भ:**
   - युवा कुंठाएं कथित हाशिए पर, रोजगार की कमी और अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व **से उपजी हो सकती हैं**।
   - उच्चाधिकार प्राप्त समितियां और कोटा जैसे नीतिगत उपाय आंशिक उपाय हैं, लेकिन राज्य के दर्जे की आकांक्षाओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं।
4. **सुरक्षा निहितार्थ:**
   - लद्दाख की सीमा चीन से लगा हुआ है, जिससे नागरिक अशांति एक **रणनीतिक चिंता का विषय** बन गई है।
   - सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हिंसा सीमावर्ती **केंद्र शासित प्रदेशों में** नागरिक-सैन्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता का संकेत देती है।
5. **नीति और प्रशासन के लिए सबक:**
   - तनाव बढ़ने से पहले **युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों के साथ निरंतर जुड़ाव** का महत्व।
   - केंद्र शासित प्रदेश राज्य के दर्जे के लिए संवैधानिक विकल्पों पर स्पष्टता **की आवश्यकता**।
   - कट्टरपंथ को रोकने के लिए **उच्चाधिकार प्राप्त समितियों** के उपयोग को **जमीनी स्तर पर परामर्श** के साथ पूरक किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

लद्दाख की अशांति भारत में **क्षेत्रीय आकांक्षाओं, युवा सक्रियता और संवैधानिक प्रावधानों के बीच जटिल परस्पर क्रिया** को दर्शाती है । जबकि केंद्र सरकार ने **उच्चाधिकार प्राप्त समिति** के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की है, हिंसक प्रकोप नीति वितरण और सार्वजनिक धारणा के बीच के अंतर को उजागर करता है। शासन के लिए, यह घटना **विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय संवाद, समय पर शिकायत निवारण और प्रभावी सुरक्षा योजना** की आवश्यकता को रेखांकित करती है। रणनीतिक रूप से, संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से ऐसी आकांक्षाओं को पूरा करना **लद्दाख में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा**।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में लेह विरोध प्रदर्शनों ने केंद्र शासित प्रदेशों में शासन में चुनौतियों पर प्रकाश डाला। निम्नलिखित में से कौन साकथनसहीहै?

(a) संघराज्यक्षेत्रों के पास राज्यों की तरह पूर्ण विधायी शक्तियां हैं

(b) एलएएचडीसीकेपास छठी अनुसूची जैसे उपबंधों के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं

(c) संघराज्यक्षेत्रों में स्वायत्त परिषदें नहीं हो सकती हैं

(d) संघराज्यक्षेत्रों की कानून और व्यवस्था का प्रबंधन पूरी तरह से केन्द्र द्वारा किया जाता है

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हितों के लिए लद्दाख जैसे सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक अशांति के प्रभावों पर चर्चा करें। पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। **(250 शब्द)**

Page 04 :GS 2 : International Relations / Prelims

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) 2025 **के मौके पर** 20 समान विचारधारा वाले ग्लोबल साउथ देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक **की मेजबानी की**, जिसमें **मजबूत बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधारों** की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री **एस. जयशंकर** ने वैश्विक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन, महामारी और व्यापार अनिश्चितताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ को इन चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

स्थैतिक संदर्भ (पृष्ठभूमि/संवैधानिक और वैश्विक ढांचा):

1. **ग्लोबल साउथ:**
   - एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका **के विकासशील देशों को संदर्भित करता** है, जो ऐतिहासिक रूप से कम औद्योगिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
   - अक्सर बहुपक्षीय मंचों पर **समान वैश्विक शासन, विकास वित्तपोषण और संप्रभुता की सुरक्षा** की वकालत करते हैं।
2. **बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली:**
   - बहुपक्षवाद तीन **या तीन से अधिक राज्यों के बीच नीतियों के समन्वय की प्रथा** है, मुख्य रूप से **संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को** जैसे संस्थानों के माध्यम से।
   - संयुक्त राष्ट्र के सुधारों पर लंबे समय से बहस हुई है, जिसमें **सुरक्षा परिषद का विस्तार, वित्त पोषण तंत्र और शांति स्थापना की दक्षता शामिल है**।
   - विकासशील देशों ने अक्सर **वैश्विक निर्णय लेने में कम** प्रतिनिधित्व महसूस किया है।
3. **भारत की पिछली व्यस्तता:**
   - भारत वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट **की मेजबानी करता है**, जिसमें वैश्विक **शासन**

Global South must work together, says Jaishankar

India hosts meet of 20 'like-minded' countries on sidelines of UNGA; External Affairs Minister says multilateralism under attack and international organisations are being rendered ineffective

Suhasini Haidar
NEW DELHI

The concept of multilateralism is "under attack", even as countries of the Global South are seeking more solutions from international organisations such as the United Nations, External Affairs Minister S. Jaishankar has said.

Speaking at a specially convened "high-level meeting of like-minded Global South countries" in New York on Tuesday, Mr. Jaishankar pitched for more consultations between developing countries and a joint push for UN reforms.

He said the state of the world was a cause for concern for all countries, listing a number of "shocks", including the pandemic, conflicts in Ukraine and Gaza, climate change, and trade uncertainties. He also called for an "urgent resolution of conflicts that are impacting food, fertilizer and energy security". Twenty countries took part in the meeting hosted by India, including 10 at the Ministerial level.

"In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the Global South would turn to multilateralism for solutions," Mr. Jaishankar said. "Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. The very concept of multilateralism is under attack. International organisations are being rendered ineffective or starved of resources," he added.

Nine countries from Asia, five from the Americas (South and North, including the Caribbean), and six from Africa took part in the meeting held on the sidelines of the UN General Assembly. Only Sri Lanka, the Maldives, and Mauritius were present from India's neighbourhood among the group. The meeting was the first of its kind, although officials did not confirm whether India now planned to hold such meetings regularly. India has hosted the "Voice of Global South Summit" in which about 125 countries have been invited for the past three years. It is unclear why the 20 countries present at the UN meeting had been chosen as "like-minded" rather than others, and whether more others had also been invited but declined due to scheduling issues.

The countries represented at the meeting included Bahrain, Indonesia, Qatar, Singapore, and Vietnam from Asia; St. Lucia, Trinidad and Tobago, Cuba, and Jamaica from North America; Suriname from South America; and Chad, Ghana, Lesotho, Morocco, Nigeria, and Somalia from Africa.

Mr. Jaishankar did not name any country for the "attacks on multilateralism", but his comments came a day after U.S. President Donald Trump's UNGA address. In his address, Mr. Trump criticised the UN system for not delivering peace in various conflicts, claiming he had resolved seven conflicts in the past few months, including the India-Pakistan conflict, without any help from the UN.

The U.S. has drastically cut its funding for the UN this year and withdrawn from several UN organisations, including the UN Human Rights Council and UNESCO. It has called for a review of other memberships in the UN system.

On one platform: External Affairs Minister S. Jaishankar speaks at a high-level meeting of like-minded Global South countries in New York on Wednesday. ANI

सुधारों, विकास और सहयोग पर चर्चा करने के लिए लगभग 125 देशों को आमंत्रित किया गया है।
- भारत आधुनिक वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व बैंक** और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार कीवकालतकरताहै।

वर्तमान संदर्भ (तत्काल घटनाएँ):

1. **स्पर्धा विवरण:**
   - स्थान: **न्यूयॉर्क**, यूएनजीए 2025 के दौरान।
   - प्रतिभागी: एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 20 देश; 10 ने **मंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व किया**।
   - उल्लेखनीय देश: बहरीन, इंडोनेशिया, कतर, सिंगापुर, वियतनाम, सेंट लूसिया, क्यूबा, चाड, घाना, नाइजीरिया, मोरक्को, सोमालिया, अन्य।
2. **उठाए गए प्रमुख मुद्दे:**
   - वैश्विक झटके: **महामारी, यूक्रेन और गाजा संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, व्यापार अनिश्चितताएं**।
   - भोजन, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा **पर समाधान की तत्काल आवश्यकता**।
   - वर्तमान बहुपक्षवाद की आलोचना: **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की** अप्रभावीताऔरसंसाधनबाधाएं।
3. **अंतर्निहित ड्राइवर:**
   - संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता **को कमजोर करने वाली एकतरफा या प्रमुख शक्तियों के खिलाफ पुशबैक** (संदर्भ: अमेरिकी वित्त पोषण में कटौती और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से वापसी)।
   - अंतर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने और वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए ग्लोबल साउथ देशों के बीच **सामूहिक सौदेबाजी** की आवश्यकता।

विश्लेषण:

1. **राजनयिक/रणनीतिक महत्व:**
   - ग्लोबल साउथ में **भारत के नेतृत्व** और वैश्विक शासन में सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करता है।
   - भारत की सॉफ्ट पावर **को बढ़ाता** है और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका **में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता** है।
2. **तनाव में बहुपक्षवाद:**
   - जयशंकरकाबयानएकतरफावादऔरवैश्विकमानदंडोंकेक्षरण**केबारेमें चिंताओं को दर्शाता है**, उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ चुनिंदा अमेरिकी जुड़ाव।
   - प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने के लिए वैश्विक संस्थानों में **संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता** पर प्रकाश डाला
3. **वैश्विक दक्षिण सहयोग:**
   - जलवायु कार्रवाई, संघर्ष समाधान, व्यापार न्याय और न्यायसंगत विकास **जैसे मुद्दों पर स्थिति को मजबूत करता है**।
   - समान विचारधारा वाले देशों को **यूएनजीए वार्ताओं और वैश्विक आर्थिक मंचों पर समन्वय करने के लिए** एक मंच प्रदान करता है।
4. **वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ:**
   - संयुक्त राष्ट्र और उसके वित्त पोषण में कटौती की अमेरिकी आलोचनाओं **के बीच** , ग्लोबल साउथ सहयोग **वैश्विक शासन में संतुलन प्रदान करता है**।
   - यह बहुपक्षवाद को छोड़ने के बजाय उसमें सुधार करने के भारत के एजेंडे **को दर्शाता** है , जो एकतरफा शक्तियों से अपने दृष्टिकोण को अलग करता है।

निष्कर्ष

दैनिक समाचार विश्लेषण

भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल साउथ बैठक बहुध्रुवीय दुनिया में अपने हितों की रक्षा के लिए **विकासशील देशों के बीच सहयोगात्मक कूटनीति के महत्व** को रेखांकित करती है। बहुपक्षीय संस्थानों को चुनौतियों का सामना करने के साथ, **ग्लोबल साउथ देशों को** संयुक्त राष्ट्र सुधारों, न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और प्रभावी संघर्ष समाधान तंत्र **की वकालत करने के लिए एकजुट होना चाहिए**। भारत की नेतृत्व भूमिका इसकी **राजनयिक परिपक्वता और समावेशी वैश्विक शासन के प्रति प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाती है**, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: "ग्लोबल साउथ" शब्द मोटे तौर पर संदर्भित करता है:

(a) दक्षिणी गोलार्ध के विकसित देश

(b) एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश

(c) केवल अफ्रीकी देश

(d) केवल लैटिन अमेरिकी देश

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जांच करें कि विकासशील देश सामूहिक रूप से जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और संघर्ष समाधान जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ में भारत की पहल के बारे में बताएं। **(150 शब्द)**

Page 06 : GS 2 : Social Justice/ Prelims

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी **की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने 2028-29 **तक पूरे भारत में** 5,000 स्नातकोत्तर (पीजी) और 5,023 स्नातक (यूजी) मेडिकल सीटें **जोड़ने के लिए** केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण **को मंजूरी दी**। यह योजना **मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों**, **स्टैंडअलोन पीजी संस्थानों और अस्पतालों को मजबूत करने पर केंद्रित है**, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ उपलब्धता को बढ़ाना है।

स्थैतिक संदर्भ:

1. **भारत में चिकित्सा शिक्षा:**
   - भारत में वर्तमान में 1,23,700 **एमबीबीएस सीटों** के साथ 808 **मेडिकल कॉलेज हैं**।
   - पिछले एक दशक में, 69,352 **एमबीबीएस सीटें** (127% वृद्धि) और 43,041 **पीजी सीटें**

Centre clears scheme to add medical seats across country

5,000 postgraduate and 5,023 undergraduate medical seats to be added; existing medical colleges, standalone postgraduate institutes, and hospitals run by the governments will be upgraded

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, on Wednesday approved Phase 3 of a Centrally sponsored scheme that will add 5,000 postgraduate and 5,023 undergraduate medical seats in the country by 2028-29.

Under the scheme, existing medical colleges, standalone postgraduate institutes, and hospitals run by the Union and the State governments will be strengthened and upgraded at an enhanced cost ceiling of ₹1.5 crore a seat.

The Union government said the initiative would significantly augment the number of MBBS seats and availability of specialist doctors by creating additional postgraduate seats, and enable introduction of new specialties across government medical institutions.

"This will strengthen the overall availability of doctors in the country," the Health Ministry said in a press release.

The total financial implications of these two schemes is ₹15,034.5 crore from 2025-26 to 2028-29. The Central share is ₹10,303.20 crore and the States' ₹4,731.30 crore.

"The target of these schemes is to increase 5,000 PG seats and 5,023 UG seats in government institutions by 2028-2029," the Ministry added.

Detailed guidelines will be issued by the Union Health and Family Welfare Ministry for implementation of the schemes. Currently, India has 808 medical colleges with 1,23,700 MBBS seats.

Over the past decade, 69,352 MBBS seats have been added, a growth of 127%. Similarly, a total of 43,041 postgraduate seats have been added, a 143% rise.

"Despite the addition, certain regions in India still need to enhance capacities to match the demand, access and affordability of healthcare," the Ministry said. Further, there are 22 All India Institutes of Medical Sciences approved under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.

"Apart from providing tertiary healthcare services, they also play an important role in building a pool of health professionals with highest standards of medical competence with their latest teaching learning facilities," the Ministry said.

A more inclusive and competency-based Qualifications of Faculty Regulation issued, says Ministry

Faculty eligibility

The New Medical Institution (Qualifications of Faculty) Regulations 2025 have been issued by adopting a more inclusive and competency-based approach to faculty eligibility and recruitment. These changes aim to address the growing requirement of teaching personnel and meeting the academic and professional standards, it added.

Improving conditions

The chart shows the number of medical colleges in India over the years and the number of MBBS seats they offer

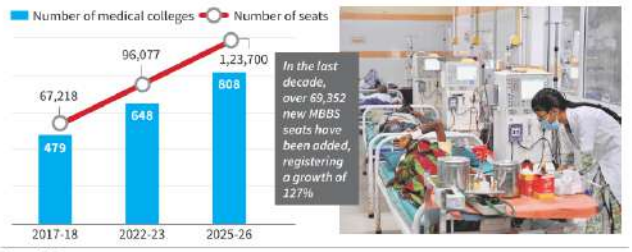

Source: PIB

(143% वृद्धि) जोड़ी गई हैं।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) **तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।

2. **केंद्र प्रायोजित योजनाएं:**
   - इन्हें केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित **किया जाता है**, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी अधिक होती है।
   - चरण 3 की **कुल लागत** ₹15,034.5 **करोड़ है**, जिसमें केंद्र का **योगदान** ₹10,303.2 **करोड़** और राज्यों का ₹4,731.3 **करोड़ है**।
   - यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 **के अनुरूप है**, **जो** समान पहुंच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डॉक्टर-रोगी अनुपात में वृद्धि **पर जोर देती है**।
3. **संकाय विनियम:**
   - **नए चिकित्सा संस्थान** (**संकाय की योग्यता**) **विनियम** 2025 शिक्षण कर्मियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए **योग्यता-आधारित**, **समावेशी भर्ती** पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

वर्तमान संदर्भ:

1. **कार्यान्वयन योजना:**
   - मौजूदा संस्थानों को 1.5 **करोड़ रुपये प्रति सीट की लागत सीमा पर अपग्रेड किया जाएगा**।
   - नई विशिष्टताओं, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में क्षेत्रीय संतुलन **और** वंचित क्षेत्रों में **विशेषज्ञ डॉक्टरों को बढ़ाने** पर ध्यान केंद्रित करें।
2. **स्वास्थ्य देखभाल अंतराल:**
   - कुछ क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त चिकित्सा क्षमता का अभाव है।
   - सरकारी संस्थानों में सीटें बढ़ाने से **स्वास्थ्य सेवा की पहुंच**, **सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार होगा**, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

मुख्य के लिए विश्लेषण:

1. **सामरिक महत्व:**
   - स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे **को बढ़ाता है और** विशेषज्ञ डॉक्टरों **की कमी को दूर करता** है।
   - चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में **क्षेत्रीय असमानताओं को** कम करता है।
2. **शैक्षिक प्रभाव:**
   - जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए **प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों के पूल का** विस्तार करना।
   - योग्यता-आधारित संकाय भर्ती **बेहतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और पेशेवर मानकों को सुनिश्चित करती है**।
3. **आर्थिक निहितार्थ:**
   - केंद्र और राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण निवेश **रोजगार सृजन**, **कौशल विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में योगदान देता है**।
   - दीर्घकालिक लाभों में **मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम** और निजी स्वास्थ्य देखभाल पर **निर्भरता कम करना शामिल है**।

निष्कर्ष

मेडिकल सीटों का चरण 3 का विस्तार **भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और समान चिकित्सा शिक्षा की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है**। यूजी और पीजी सीटों को बढ़ाकर, बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और संकाय मानदंडों को संशोधित करके,

इस योजना का उद्देश्य **क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना**, **स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में वृद्धि करना और सभी** नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने **के भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित करते हुए डॉक्टरों और विशेषज्ञों का एक मजबूत पूल बनाना है**।

Page 06 : GS 2 : Social Justice/ Prelims

प्रश्न: भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के चरण 3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 2028-29 तक 5,000 स्नातकोत्तर और 5,023 स्नातक मेडिकल सीटें जोड़ देगा।

2. यह योजना पूरी तरह से नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर केंद्रित है।

3. केंद्र 10,303.2 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जबकि राज्य 4,731.3 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में योग्यता-आधारित संकाय नियमों की भूमिका का विश्लेषण करें। ये सुधार भारत के व्यापक स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होते हैं? **(150 शब्द)**

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page : 07: GS 3 : Science and Tech/ Prelims

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से भारत के ऊर्जा परिदृश्य को आकार दे रहा है। जबकि एआई **कुशल ऊर्जा प्रबंधन, नवीकरणीय एकीकरण और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का वादा करता है**, इसकी अपनी **डेटा और कंप्यूटिंग आवश्यकताएं** - मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर डेटा केंद्रों के माध्यम से - भारत के पहले से ही तनावग्रस्त पावर ग्रिड के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, वैश्विक एआई-संचालित ऊर्जा मांग 2030 तक चौगुनी हो सकती है, भारत के डेटा सेंटर बिजली की खपत सालाना **40-50 TWh बढ़ने का अनुमान है**।

स्थैतिक संदर्भ:

1. **भारत की ऊर्जा प्रोफाइल:**
   - चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता

Will AI fix India's energy demand or will its own needs snowball?

A report estimates that annual global demand for data centre capacity may increase by 19 to 22% from 2023 to 2030, reaching 171 to 219 GW compared to the current demand of 60 GW; this would require building twice the capacity built since 2000 within a quarter of that time frame

T.V. Padma

As artificial intelligence (AI) and its attendant data demand continue to expand in India and worldwide, a curious dilemma has arisen: will AI help transform energy delivery for the better or will the data centres crucial to its operations impose a new burden on the world's power grid?

In a 2024 report, the International Energy Agency (IEA) highlighted the growing interconnections between energy and AI worldwide. It projected that demand from data centres would more than double by 2030 to around 945 TWh and that AI would be the principal driver. The demand from AI-optimised data centres was projected to more than quadruple by 2030.

A McKinsey report has also estimated that the annual global demand for data centre capacity could rise at 19-22% from 2023 to 2030, reaching 171-219 GW, against the total current demand of 60 GW. To avoid a deficit, at least twice as much data centre capacity built since 2000 will have to be in place in less than a quarter of the time.

Given AI's significant hunger for computing power, energy demand is naturally increasing, Anwesha Sen, an assistant programme manager at Takshashila University studying the impact of technology policy and AI on society, said. She is, however, optimistic that it's "not as drastic when compared to other energy-intensive industries".

Worldwide, data centres consume 1-2% of total power and that's expected to increase to 3-4% by 2030. To compare, the steel industry consumes around 7% of total power, Ms. Sen said.

Pressure, and potential

According to McKinsey, India's data centre demand is projected to increase from 1.2 GW in 2024 to 4.5 GW by 2030, driven largely by AI and digital adoption across sectors.

Mumbai accounts for 41% of the data centre capacity, followed by Chennai (23%) and the National Capital Region (14%).

AI-driven data centres in India are projected to consume an additional 40-50 TWh of electricity annually by 2030, according to Raghu Raman, Professor and Dean at the School of Business at Amrita Vishwa Vidyapeetham.

The increasing adoption of AI and digital technologies in India is contributing to a significant rise in energy demand, especially in already energy-intensive sectors like real estate, Vimal Nadar, national director of research at the Mumbai-based India office of Colliers, a global investment company, said. India is the third largest energy consumer worldwide, after China and the U.S., with coal, crude oil, and natural gas comprising the bulk of its energy mix.

The energy consumption of data centres is imposing huge pressure on energy systems worldwide, Anish De, global head for Energy, Natural Resources, and Chemicals at KPMG, said, adding: "India will not be any different."

According to Ms. Sen, an equal concern is the correspondingly increasing demand for freshwater required to cool the servers in these data centres.

That said, there is scope to press AI to the service of smarter energy management as well.

"AI is playing a pivotal role in transforming how energy is delivered, utilised, and managed, both globally and within India," Mr. Nadar said.

On the one hand, AI could help develop energy transition technologies and as well as new materials that mitigate India's dependence on critical minerals it currently has to import from abroad, Dr. De said by way of example.

"It will also aid faster project development. This is already playing out in the main geographies and will propagate to others quickly," he added. "We will see energy efficiency and resource efficiency gains that will also be substantial, though not enough to offset the demand. AI itself will support the gains in expansion of clean energy."

On the flip side, carbon emissions will also increase. "Despite best efforts it is practically impossible to meet this demand from renewables, both from quality and quantity standpoints," according to Dr. De.

The IEA also noted in its report that AI "could intensify some energy security strains" as "cyberattacks on energy utilities have tripled in the past four years and become more sophisticated because of AI," even as AI tools are becoming critical for energy companies to defend against such attacks.

Renewables rescue

As energy demand intensifies, real estate stakeholders are increasingly prioritising energy efficiency, sustainability, and emission reduction in both new developments and retrofitting of existing assets, Mr. Nadar said.

"Concurrently, there is a growing emphasis on renewable energy adoption. Real estate developers are increasingly incorporating rooftop solar solutions and solar-integrated building systems, further reducing the sector's reliance on conventional energy sources."

> It is practically impossible to meet this demand from renewables, both from quality and quantity standpoints
>
> ANISH DE
>
> GLOBAL HEAD FOR ENERGY, NATURAL RESOURCES, AND CHEMICALS AT KPMG

The IEA has also said a range of energy sources will be tapped to meet data centres' rising electricity needs although, according to its report, "renewables and natural gas are set to take the lead due to their cost-competitiveness and availability in key markets."

India and many other countries are taking advantage of AI to enhance energy efficiency and promote sustainable real estate practices, per Mr. Nadar. In India, the Energy Conservation Building Code and the Roadmap of Sustainable and Holistic Approach to National Energy Efficiency scheme aim to integrate AI and data analytics into smart metering, renewable energy management, and sustainable building design.

Also within the real estate sector, AI-driven solutions like smart lighting systems, predictive HVAC optimisation, and automated building controls promise to reduce energy consumption by up to 25%. Green certifications such as GRIHA and LEED further encourage AI-based monitoring of energy and resource usage.

Data centres are also adopting AI to optimise cooling systems and server utilisation. As of April 2025, nearly one-fourth of the country's total data centre capacity in major cities had been green certified, reflecting an explicit focus on creating sustainable infrastructure. Almost 67% of the Grade A office stock across India's top seven cities is also green-certified.

'Need some nudging'

Under the National Smart Grid Mission, AI-enabled systems manage demand and integrate renewables, enhancing grid reliability while reducing wastage, according to Raman. The Nxtra (Airtel) Data Centres use AI-powered cooling and predictive analytics to cut energy use, paired with renewable power purchase agreements to run green data centres. BrightNight's PowerAlpha AI deployed in India to forecast and optimise hybrid solar-wind-battery plants and ensure 24/7 access to renewable energy while minimising grid stress.

Tata Power ReNew Power and Hindustan Zinc both use AI for real-time load forecasting, reducing outages and optimising power supply in Mumbai, Dr. Raman added. BESCOM in Karnataka has also started using AI to detect faults and 'heal' grid sections and thus mitigate downtime. Similarly, smart meters in Uttar Pradesh have been using AI to detect power theft as well as manage demand-side issues.

"A digital energy grid approach aims to build a unified and interoperable power infrastructure, and its potential can be amplified using AI," Ms. Sen said.

She added that companies are also working to develop "sustainable AI" that uses recycled water and has higher power use efficiency.

"As the race to build the most capable AI systems has got companies investing in massive data centres, a transition of the energy grid itself to use more sustainable power sources is required and might need some nudging by governments," Ms. Sen said.

(T.V. Padma is a science journalist in New Delhi. tvpadma_10@yahoo.co.in)

AI has been deployed in India to forecast and optimise hybrid solar-wind-battery plants and ensure 24/7 access to renewable energy while minimising grid stress. ALESSANDRO VENTURI/UNSPLASH

- मुख्य रूप से **कोयला, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस** पर निर्भर है, हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है।
- **ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में** रियल एस्टेट, स्टील और भारी विनिर्माण शामिल हैं।

2. **एआई और ऊर्जा नेक्सस:**
   - एआई का उपयोगस्मार्टग्रिड, नवीकरणीयएकीकरण, पूर्वानुमानितरखरखावऔर ऊर्जा अनुकूलन **में किया जाता है**।
   - डेटा सेंटर आज वैश्विक बिजली का 1-2% **उपभोग करते हैं**, जिसके 2030 तक 3-4% तक बढ़ने की उम्मीद है।
3. **नियामक ढांचे:**
   - **राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन** और **ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)** एआई-सक्षम ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देते हैं।
   - GRIHA और LEED **जैसे हरित प्रमाणपत्र** AI का उपयोग करके स्थायी भवन प्रबंधन को प्रोत्साहित करते हैं।

वर्तमान संदर्भ:

1. **डेटा सेंटर वृद्धि:**
   - भारत की डेटा सेंटर क्षमता की मांग **2024 में 1.2 गीगावॉट से बढ़कर 2030 तक 4.5 गीगावॉट** होने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से एआई-संचालित है।
   - प्रमुख केंद्रों में **मुंबई (41%),चेन्नई (23%)** और **एनसीआर (14%)** शामिल हैं।
   - पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एआई-संचालित कूलिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और नवीकरणीय एकीकरण को तैनात किया जा रहा है।
2. **एआई-संचालित ऊर्जा दक्षता:**
   - स्मार्ट ग्रिड, भविष्य कहनेवाला लोड पूर्वानुमान, और नवीकरणीय अनुकूलन (जैसे, हाइब्रिड सौर-पवन-बैटरी सिस्टम) **विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और अपव्यय को कम करते** हैं।
   - रियल एस्टेट क्षेत्र एचवीएसी अनुकूलन, स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था और स्वचालित भवन प्रबंधन **के लिए एआई का उपयोग करते हैं**, जिससे संभावित रूप से ऊर्जा उपयोग 25% तक कम हो **जाता है**।
3. **चुनौतियाँ और जोखिम:**
   - सर्वर कूलिंग के लिए बिजली की बढ़ती मांग और **मीठे पानी का उपयोग**।
   - नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के बावजूद **कार्बन उत्सर्जन** में संभावित वृद्धि।
   - ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए एआई-प्रेरित साइबर सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं।

मुख्य के लिए विश्लेषण:

1. **अवसर:**
   - एआई ऊर्जावितरणकोअनुकूलित**करसकताहै,** स्वच्छऊर्जासंक्रमण**का समर्थन कर सकता है और** ग्रिड स्थिरता **में सुधार कर सकता है**।
   - क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता **और टिकाऊ शहरी नियोजन** को प्रोत्साहित करता है।
   - जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए **स्मार्ट और हरित बुनियादी ढांचे** की तैनाती में तेजी लाएगा।
2. **चुनौतियों:**
   - ऊर्जा-गहन डेटा केंद्रों से **बिजली ग्रिड पर अधिक बोझ पड़ने का** जोखिम है, खासकर शहरी केंद्रों में।
   - नवीकरणीय ऊर्जा की सीमित क्षमता एआई-प्रेरित मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकती है।
   - एआई विकास को टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित **करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप, विनियमों और प्रोत्साहनों की आवश्यकता है**।
3. **रणनीतिक निहितार्थ:**
   - ऊर्जा में एआई को अपनाने **से भारत के जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों** का समर्थन होता है, लेकिन अनियंत्रित विकास **नई ऊर्जा कमजोरियां पैदा कर सकता है**।

- एआई विस्तार, ऊर्जा नीति और नवीकरणीय तैनाती के बीच एकीकृत योजनाका आह्वान किया

निष्कर्ष

भारत में एआई एक **दोहरे अवसर प्रस्तुत करता है**: यह **ऊर्जा प्रबंधन को बदल सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा को अनुकूलित कर सकता है और ग्रिड दक्षता बढ़ा** सकता है, लेकिन एआई की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें ही **बिजली के बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव** डाल सकती हैं। रणनीतिक सरकारी नीतियां, टिकाऊ एआई डिजाइन और **नवीकरणीय और स्मार्ट ग्रिड को अपनाना यह** सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एआई **अतिरिक्त बोझ बनने के बजाय** ऊर्जा संक्रमण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि 2030 तक:

(a) वैश्विक स्तर पर एआई-संचालित डेटा केंद्र वर्तमान ऊर्जा मांग सेकमखपतकरेंगे

(b) डेटा सेंटर ऊर्जा खपत को चौगुना करने के लिए एआईप्रमुखचालकहोगा

(c) वैश्विकडाटासेंटर ऊर्जा खपत में भारत का योगदान 50% सेअधिकहोगा

(d) नवीकरणीय ऊर्जा भारत में एआई डेटा सेंटर की मांग को पूरी तरहसेपूराकरेगी

उत्तर: (b)

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न :भारतके ऊर्जा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। टिकाऊ ऊर्जा प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है? **(150 शब्द)**

Page 11 :GS 2 : Social Justice / Prelims

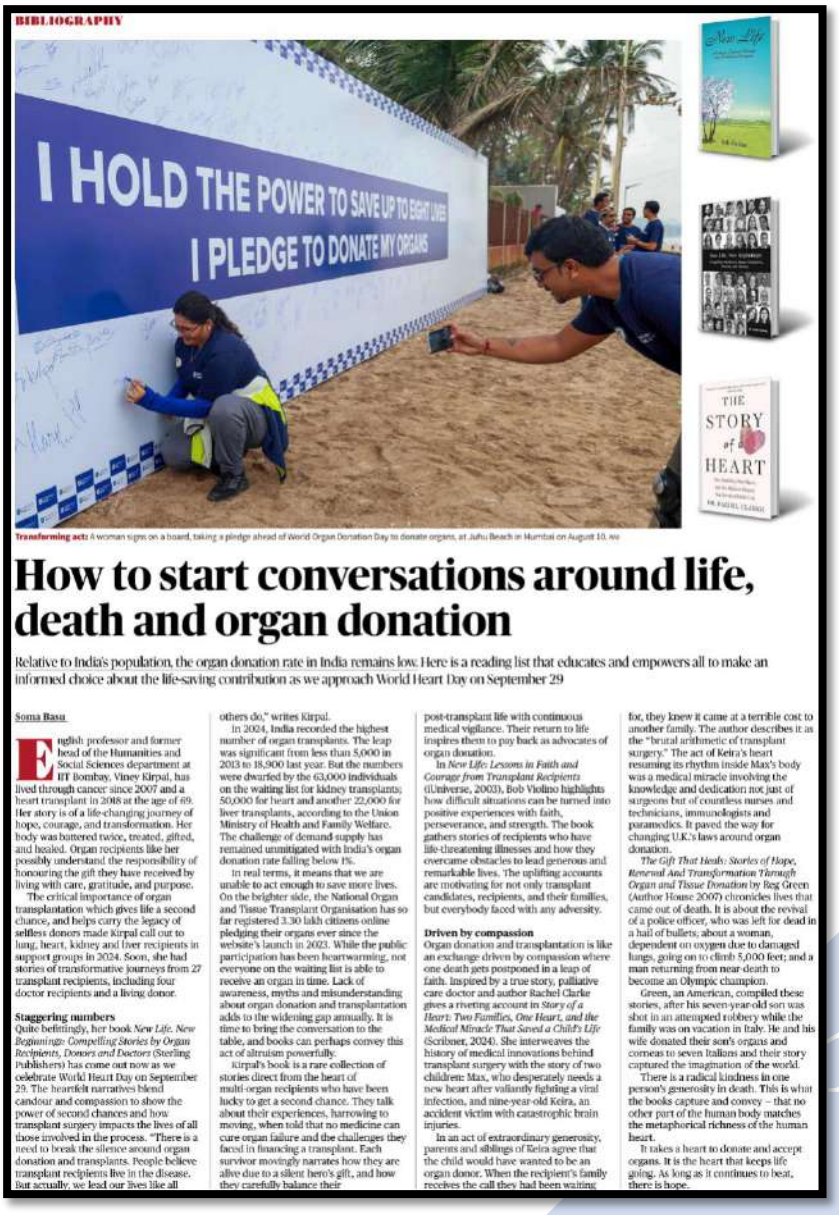

अंग दान एक जीवन रक्षक हस्तक्षेप है जो अंग विफलता से पीड़ित व्यक्तियों को जीवन में दूसरा मौका प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी और प्रत्यारोपण सर्जरी में प्रगति के बावजूद, भारत की **अंग दान दर 1% से नीचे बनी हुई है, जो** मांग और आपूर्ति के **बीच एक बड़े अंतर को उजागर करती** है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, जबकि भारत ने **2024 में 18,900 अंग प्रत्यारोपण** दर्ज किए, **63,000 से अधिक रोगी गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं**, 50,000 हृदय के लिए और 22,000 यकृत के लिए।

स्थैतिक संदर्भ:

1. **कानूनी और संस्थागत ढांचा:**

BIBLIOGRAPHY

Transforming act: A woman signs on a board, taking a pledge ahead of World Organ Donation Day to donate organs, at Juhu Beach in Mumbai on August 10.

How to start conversations around life, death and organ donation

Relative to India's population, the organ donation rate in India remains low. Here is a reading list that educates and empowers all to make an informed choice about the life-saving contribution as we approach World Heart Day on September 29

Soma Basu

English professor and former head of the Humanities and Social Sciences department at IIT Bombay, Viney Kirpal, has lived through cancer since 2007 and a heart transplant in 2018 at the age of 69. Her story is of a life-changing journey of hope, courage, and transformation. Her body was battered twice, treated, gifted, and healed. Organ recipients like her possibly understand the responsibility of honouring the gift they have received by living with care, gratitude, and purpose.

The critical importance of organ transplantation which gives life a second chance, and helps carry the legacy of selfless donors made Kirpal call out to lung, heart, kidney and liver recipients in support groups in 2024. Soon, she had stories of transformative journeys from 27 transplant recipients, including four doctor recipients and a living donor.

Staggering numbers

Quite befittingly, her book *New Life. New Beginnings: Compelling Stories by Organ Recipients, Donors and Doctors* (Sterling Publishers) has come out now as we celebrate World Heart Day on September 29. The heartfelt narratives blend candour and compassion to show the power of second chances and how transplant surgery impacts the lives of all those involved in the process. "There is a need to break the silence around organ donation and transplants. People believe transplant recipients live in the disease. But actually, we lead our lives like all others do," writes Kirpal.

In 2024, India recorded the highest number of organ transplants. The leap was significant from less than 5,000 in 2013 to 18,900 last year. But the numbers were dwarfed by the 63,000 individuals on the waiting list for kidney transplants; 50,000 for heart and another 22,000 for liver transplants, according to the Union Ministry of Health and Family Welfare. The challenge of demand supply has remained unmitigated with India's organ donation rate falling below 1%.

In real terms, it means that we are unable to act enough to save more lives. On the brighter side, the National Organ and Tissue Transplant Organisation has so far registered 3.30 lakh citizens online pledging their organs ever since the website's launch in 2023. While the public participation has been heartwarming, not everyone on the waiting list is able to receive an organ in time. Lack of awareness, myths and misunderstanding about organ donation and transplantation adds to the widening gap annually. It is time to bring the conversation to the table, and books can perhaps convey this act of altruism powerfully.

Kirpal's book is a rare collection of stories direct from the heart of multi-organ recipients who have been lucky to get a second chance. They talk about their experiences, harrowing to moving, when told that no medicine can cure organ failure and the challenges they faced in financing a transplant. Each survivor movingly narrates how they are alive due to a silent hero's gift, and how they carefully balance their post-transplant life with continuous medical vigilance. Their return to life inspires them to pay back as advocates of organ donation.

In *New Life: Lessons in Faith and Courage from Transplant Recipients* (iUniverse, 2003), Bob Violino highlights how difficult situations can be turned into positive experiences with faith, perseverance, and strength. The book gathers stories of recipients who have life-threatening illnesses and how they overcame obstacles to lead generous and remarkable lives. The uplifting accounts are motivating for not only transplant candidates, recipients, and their families, but everybody faced with any adversity.

Driven by compassion

Organ donation and transplantation is like an exchange driven by compassion where one death gets postponed in a leap of faith. Inspired by a true story, palliative care doctor and author Rachel Clarke gives a riveting account in *Story of a Heart: Two Families, One Heart, and the Medical Miracle That Saved a Child's Life* (Scribner, 2024). She interweaves the history of medical innovations behind transplant surgery with the story of two children: Max, who desperately needs a new heart after valiantly fighting a viral infection, and nine-year-old Keira, an accident victim with catastrophic brain injuries.

In an act of extraordinary generosity, parents and siblings of Keira agree that the child would have wanted to be an organ donor. When the recipient's family receives the call they had been waiting for, they knew it came at a terrible cost to another family. The author describes it as the "brutal arithmetic of transplant surgery." The act of Keira's heart resuming its rhythm inside Max's body was a medical miracle involving the knowledge and dedication not just of surgeons but of countless nurses and technicians, immunologists and paramedics. It paved the way for changing U.K.'s laws around organ donation.

The Gift That Heals: Stories of Hope, Renewal And Transformation Through Organ and Tissue Donation by Reg Green (Author House 2007) chronicles lives that came out of death. It is about the revival of a police officer, who was left for dead in a hail of bullets; about a woman, dependent on oxygen due to damaged lungs, going on to climb 5,000 feet; and a man returning from near-death to become an Olympic champion.

Green, an American, compiled these stories, after his seven-year-old son was shot in an attempted robbery while the family was on vacation in Italy. He and his wife donated their son's organs and corneas to seven Italians and their story captured the imagination of the world.

There is a radical kindness in one person's generosity in death. This is what the books capture and convey – that no other part of the human body matches the metaphorical richness of the human heart.

It takes a heart to donate and accept organs. It is the heart that keeps life going. As long as it continues to beat, there is hope.

- **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (थोटा) अंग** दान और प्रत्यारोपण को विनियमित करता है।
- **राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ)** दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री रखता है।
- जीवित दाताओं और मृत दाताओं को सख्त नैतिक और चिकित्सा दिशानिर्देशों के तहत कानूनी रूप से अनुमति दी जाती है।

2. **चिकित्सा परिप्रेक्ष्य:**
   - आमतौर पर प्रत्यारोपित अंगों में गुर्दे, **यकृत, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और कॉर्निया शामिल हैं**।
   - प्रत्यारोपण के लिए **विशेषचिकित्साबुनियादीढांचे, प्रशिक्षितकर्मियोंऔरपोस्ट-ऑपरेटिवदेखभालकीआवश्यकताहोतीहै**।

वर्तमान संदर्भ:

1. **बढ़ती जागरूकता और प्रतिज्ञाएं:**
   - 2023 से, भारत में **3.30 लाख नागरिकों ने** अपने अंगों को गिरवी रखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।
   - विश्व हृदय दिवस **जैसे कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता अभियान, किताबें और मीडिया कवरेज** सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हैं।
2. **चुनौतियों:**
   - कम जागरूकता, सांस्कृतिक मिथक और धार्मिक गलतफहमियां दान दरों को कम करती हैं।
   - मांग आपूर्ति से काफी अधिक है, जिससे **लंबी प्रतीक्षा सूची और रोकथाम योग्य मौतें होती हैं**।
   - वित्तीय और तार्किक बाधाएं प्रत्यारोपण को कई लोगों के लिए दुर्गम बना देती हैं।
3. **मानव कहानियाँ और वकालत:**
   - प्राप्तकर्ताओं और दाताओं के आख्यान, जैसे विनी कृपाल काअनुभव, अंग**दानकोमानवीयबनाते**हैंऔरपरोपकारिता को प्रेरित करते हैं।
   - अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, जैसे कि रेग ग्रीन का परिवार और यूके के कानूनी सुधार, दान के परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।

मुख्य के लिए विश्लेषण:

1. **नीतिगत निहितार्थ:**
   - जन जागरूकता अभियानों **को मजबूत करने,** स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम **में अंग दान को एकीकृत करने** और दाता प्रतिज्ञाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
   - राज्यों में सरकार समर्थित अंग प्रत्यारोपण बुनियादी ढांचे **का विस्तार करने से** पहुंच में सुधार हो सकता है।
   - गैर सरकारी संगठनों और रोगी वकालत समूहों **के साथ सहयोग सूचना** अंतर को पाट सकता है।
2. **सामाजिक प्रभाव:**
   - अंग दान सहानुभूति और एकजुटता की संस्कृति **को बढ़ावा देता है**, व्यक्तिगत नुकसान को सामाजिक लाभ में बदल देता है।
   - नैतिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देता है और **परिवार की सहमति और परामर्श के महत्व पर प्रकाश डालता है**।
3. **वैश्विक सबक:**
   - स्पेन और यूके **जैसे देशों में** ऑप्ट-आउट फ्रेमवर्क, कुशल रजिस्ट्रियों और मजबूत जागरूकता कार्यक्रमों **के कारण सफल अंग दान प्रणाली है**।
   - भारत दान दरों को बढ़ाने के लिए **नीति, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक जुड़ाव में सर्वोत्तम प्रथाओं** को अपना सकता है।

निष्कर्ष

अंगदान एक चिकित्सा प्रक्रिया से कहीं अधिक है; यह **करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का** एक गहरा कार्य है। भारत को **अंगों की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है**। कानूनी ढांचे और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ-साथ, **सार्वजनिक जागरूकता, व्यक्तिगत कहानियां और सांस्कृतिक स्वीकृति** एक स्थायी अंग दान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पंजीकृत दाता और सूचित चर्चा **जीवन बचाने और** प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हजारों लोगों को आशा देने में योगदान देती है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में अंग दान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत की अंगदान दर जनसंख्या के 1% से भी कम है।

2. राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) अंग दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की एकरजिस्ट्रीरखताहै।

3. गुर्दे, यकृत, हृदय, फेफड़े और कॉर्निया आमतौर पर प्रत्यारोपित अंग होते हैं।

सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर: d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में अंग की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर का गंभीर विश्लेषण करें। नैतिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए इस अंतर को पाटने के उपाय सुझाएं। **(150 शब्द)**

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page : 09 Editorial Analysis

दैनिक समाचार विश्लेषण

Follow the rains, not the calendar, to fight floods

Pratha Mishra

Research Analyst, Council on Energy, Environment and Water. Views are personal

Nitin Bassi

Fellow, Council on Energy, Environment and Water. Views are personal

Each year, urban India braces for the monsoon – contractors are deployed, drains desilted, and emergency protocols rehearsed. Yet, when the rain finally arrives – often untimely and more intense than expected – headlines are dominated by flooded roads, waterlogged homes, and stranded commuters. The deeper issue is that our cities are often still designed for a climate that no longer exists.

Northern States are seeing heavy flooding even in September, with all of Punjab's 23 districts being hit by floods. Delhi and Gurugram have been inundated by intense rains, and Uttarakhand and Himachal Pradesh are experiencing frequent cloudbursts. In the east, Kolkata is facing torrential rains.

Timing, amount, and intensity

But the rains came early too. In May, Mumbai recorded 135.4 mm of rainfall in just 24 hours, followed by 161.9 mm the next day. Delhi recorded 81 mm fall within a few hours on the same day, overwhelming the drainage systems. This shift in rainfall timings is not new; yet our preparedness remains tethered to outdated schedules. Drain cleaning, for instance, still follows the June monsoon calendar.

Cities must follow the rain to be able to bridge the gap between schedules, and readiness and reality. An analysis by the Council on Energy, Environment and Water shows that about 64% of Indian tehsils have seen a rise in the frequency of heavy rainfall days by 1-15 days, especially in Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, and Karnataka. The consequences for urban systems are significant, from localised flooding to disruptions in essential services. In the last two decades, floods have caused most of the loss to life and property from natural disasters in India. Today, a single flood can cause damages of some ₹8,700 crore, with such events becoming increasingly frequent.

Indian cities are often designed for a climate that no longer exists

The challenge is not just the amount of rainfall, but also the intensity. Intensity, Duration, Frequency (IDF) curves, which track rainfall patterns over time, offer an interesting picture. For instance, CEEW's analysis of daily rainfall from 1970 to 2021 in the coastal city of Thane shows that one-hour rainfall now reaches 50 mm once every two years, and about 80 mm per hour once every 50 years. This means such heavy rainfall can be expected to occur within hours, leaving little room for cities to respond. There is also a sharp difference between how much rain falls in one hour versus three hours, revealing that rainfall that once spread across a day may now have a higher chance of falling within an hour. We propose three interlinked actions to prepare Indian cities better for the monsoons and flood-proof them.

Preparing for the monsoon

First, city authorities should incorporate sub-daily rainfall analysis into city monsoon planning. Municipalities must move beyond long-term averages and integrate recent patterns and short-duration, high-intensity rainfall events that unfold within a few hours, into infrastructure design. Real-time data on sub-daily rainfall, which occurs over intervals shorter than 24 hours, must inform citizens about drainage operations and upgrades. For instance, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has announced this year that it will widen its drains to handle up to 120 mm of rainfall in an hour.

While India's monsoon officially spans 100-120 days, just a few hours of intense rain across select days account for most of the seasonal rainfall. Yet, maintenance and planning assume a uniform spread. This illusion of consistency leads to systems that fail not due to excessive seasonal totals, but hourly extremes. Recognising this compression is the first step towards resilience.

Second, align cleaning of storm water drains and municipal solid waste management calendars. An overlooked cause of urban flooding is unmanaged waste – plastic, debris, and litter frequently block drains. Yet storm water and waste are handled by separate departments on different schedules. While the Ministry of Housing and Urban Affairs recommends drain cleaning before, during, and after the monsoon, its effectiveness hinges on coordination with waste collection. Even a freshly cleaned drain can clog again if garbage is left uncollected nearby. Ideally, storm water and sanitation departments must coordinate, especially during high-risk periods. Rainfall alerts from the India Meteorological Department should automatically trigger joint sanitation drives and drain inspections in vulnerable areas. In Vijayawada, such coordination – through monsoon response teams composed of officials from the sanitation, engineering, and planning departments – has reduced waterlogging and eased conditions for residents.

Third, city authorities must update IDF curves every 5-10 years to ensure that infrastructure keeps pace with evolving rainfall patterns. Without this, new drainage systems will continue to rely on outdated data, leaving them ill-equipped to handle present day storm water run-off volumes. In response to recent intensifying rains, the BMC has also proposed expanding storm water capacity and preparing a new drainage master plan based on updated trends. Drainage design should also be based on micro-catchment-level hydrological analysis that accounts for topography, which affects peak discharge during storms. New systems must be separated from the sewerage networks to avoid overload and ensure efficiency. We are not losing to the rain, but to the idea that the rain fits into seasonal boxes. Instead of asking when the monsoon will begin, we need to ask, are we prepared for the rain already falling?

GS. Paper 03- आपदाप्रबंधन

UPSC Mains Practice Question: तैयारियों के बावजूद शहरी भारत को बार-बार बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों पर चर्चा करें और शहरी बाढ़ लचीलापन बढ़ाने के उपाय सुझाएं। (150 शब्द)

दैनिक समाचार विश्लेषण

संदर्भ:

प्री-मॉनसून तैयारियों के बावजूद शहरी भारत को हर मानसून में बार-बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण वर्षा **के पैटर्न में बदलाव** के कारण निश्चित मानसून कैलेंडर **पर आधारित पारंपरिक योजना अपर्याप्त हो गई है** । **उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और** मुंबई, दिल्ली और कोलकाता **में भारी बारिश सहित हाल की घटनाएं दर्शाती हैं कि भारतीय शहर** असामयिक और उच्च तीव्रता वाली वर्षा **के लिए तैयार नहीं हैं**, जिससे बुनियादी ढांचे की विफलता, आर्थिक नुकसान और मानव हताहत हो सकते हैं।

स्थैतिक संदर्भ:

1. **शहरी बाढ़ भेद्यता:**
   - पर्याप्त वर्षा जल प्रबंधन प्रणालियों **के बिना भारतीय शहरों का तेजी से विस्तार हुआ है**।
   - खराब **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** नालियों को अवरुद्ध करता है, जिससे शहरी बाढ़ बढ़ जाती है।
   - ड्रेनेज सिस्टम ऐतिहासिक वर्षा डेटा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, न कि **तीव्र छोटी अवधि की घटनाओं के लिए**।
2. **आर्थिक और मानवीय लागत:**
   - भारत में प्राकृतिक आपदाओं के बीच जान-माल के नुकसान **का प्रमुख कारण बाढ़ है** ।
   - एक भी शहरी बाढ़ की घटना से **8,700 करोड़ रुपये या उससे अधिक** का नुकसान हो सकता है।
3. **प्रासंगिक संस्थागत ढांचा:**
   - **आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)** नगरपालिका बाढ़ की तैयारी के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
   - **भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) वर्षा** की चेतावनी जारी करता है, लेकिन नगरपालिका कार्रवाई के साथ एकीकरण अक्सर कमजोर होता है।

वर्तमान संदर्भ:

1. **वर्षा के पैटर्न में बदलाव:**
   - उप-दैनिक वर्षा की तीव्रता में वृद्धि हुई है; शहरों को अब हर **50 साल में एक बार 80 मिमी/घंटा की घटनाओं** का सामना करना पड़ता है, जो पहले एक दिन में होता था।
   - हाल के दशकों में **64% भारतीय तहसीलों में** भारी वर्षा की आवृत्ति में 1-15 दिनों की वृद्धि दर्ज की गई है।
2. **मामले का अध्ययन:**
   - **मुंबई: बीएमसी ने** 120 मिमी प्रति घंटे की बारिश **के लिए नालों को चौड़ा करने की योजना बनाई** है।
   - **विजयवाड़ा:** समन्वित मानसून प्रतिक्रिया दल स्वच्छता, तूफान के पानी और योजना विभागों **को एकीकृत करके जलभराव को कम करते हैं**।
3. **शहरी लचीलेपन के लिए सिफारिशें:**
   - बुनियादी ढांचे की योजना में **उप-दैनिक वर्षा डेटा** को शामिल करें।
   - नाली की रुकावटों को रोकने के लिए **तूफानी जल और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को** संरेखित करें।
   - हर 5-10 साल में तीव्रता की अवधि-आवृत्ति (आईडीएफ) **को अपडेट करें और** सूक्ष्म जलग्रहण स्तर **पर जल निकासी प्रणालियों को डिजाइन** करें।
   - ओवरलोड को रोकने के लिए तूफानी पानी की नालियों को सीवर नेटवर्क से अलग करें।

मुख्य के लिए विश्लेषण:

दैनिक समाचार विश्लेषण

1. **नीतिगत निहितार्थ:**
   - शहरी बाढ़ योजना को **कैलेंडर-आधारित मानसून की तैयारी से वर्षा-उत्तरदायी प्रबंधन में बदलना चाहिए**।
   - **स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जीआईएस-आधारित बाढ़ मानचित्रण में निवेश** आवश्यक है।
   - नगर पालिकाओं को **उच्च जोखिम वाली वर्षा की घटनाओं का कुशलतापूर्वक जवाब देने के लिए** अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता होती है।
2. **सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:**
   - अप्रबंधित बाढ़ **परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सेवाओं को बाधित करती है**।
   - बाढ़ प्रतिरोधी शहरी नियोजन **सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और जलवायु अनुकूलन को बढ़ाता है**।
3. **वैश्विक और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य:**
   - टोक्यो और सिंगापुर **जैसे शहर** वास्तविक समय में वर्षा की निगरानी, एकीकृत जल निकासी डिजाइन और नागरिक चेतावनी प्रणाली का उपयोग करते हैं।
   - भारत एआई-आधारित बाढ़ पूर्वानुमान और स्मार्ट जल प्रबंधन सहित **प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान** अपना सकता है।

निष्कर्ष

भारत में शहरी बाढ़ अब एक अनुमानित मानसून घटना नहीं है, बल्कि **जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से प्रेरित एक जटिल चुनौती है**। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, शहरों को **बारिश का पालन करना चाहिए, न कि कैलेंडर का पालन** करना - वास्तविक समय में वर्षा डेटा, अंतर-विभागीय समन्वय और अद्यतन बुनियादी ढांचे के डिजाइन को एकीकृत करना। प्रभावी बाढ़ की तैयारी केवल मानसून के कार्यक्रम का जवाब देने के बारे में नहीं है, बल्कि **आधुनिक वर्षा पैटर्न की तीव्रता और समय के अनुकूल होना है**, जिससे शहरी भारत के लिए लचीलापन और स्थिरतासुनिश्चितहोतीहै।

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 6TH OCT 2025
PSIR
MENTORSHIP BY-NITIN KUMAR SIR
COMPREHENSIVE COVERAGE (4-5 MONTHS)
DAILY CLASSES : 2 hrs. (ONLINE CLASS)
350+ HRS . MAXIMUM: 40 STUDENTS PER BATCH.
PERIODIC DOUBT SESSION & CLASS TEST
16 SECTIONAL TEST (4 FROM EACH SECTION)
4 FULL LENGTH TEST
CHAPTERWISE PYQS DISCUSSION
CHAPTERWISE COMPILATION OF QUOTATION
DAILY ANSWER WRITING
ONE TIME PAYMENT
RS 25,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 30,000/-
www.nitinsirclasses.com
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

NITIN SIR CLASSES

प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)

- DURATION : 7 MONTH
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS

ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
सफलता बैच (Pre 2 Interview)
DURATION : 1 YEAR
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)
ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES
Nitin sir classes
Know your daily
CLASSES
TIME TABLE FOR DAILY CLASSES
• 07:30 PM - THE HINDU ANALYSIS
• 09:00 PM - Daily Q & A Session (PT + Mains)
SUBSCRIBE
HTTPS://T.ME/NITIN KUMAR (PSIR)
WWW.NITINSIRCLASSES.COM

दैनिक समाचार विश्लेषण

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**